(c) if so, what action Government propose to take to supply steel to the above industries at reasonable rate?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES & STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b). There has been no increase in the Joint Plant Committee base price or the stockyard prices of steel from the main producers since the 7th April, 1979. Prices of products of other producers are however determined by forces of demand and supply. The bars and rods required for construction are mainly produced by mini-steel plants/rerollers; and their prices have been ruling above stockyard prices due to constraints on the production and increase in demand for construction. Industrial requirements are being met predominantly by supply from main producers to actual users at fixed prices.

(c) Constant and continuous efforts are being made to increase steel production at the integrated steel plants which had been affected mainly due to inadequate supply of coal and power. Exports of various categories have also been banned and imports have also been arranged in respect of categories in short supply. End use restrictions have also been re-imposed to prevent misuse of steel by persons to whom it has been allotted for specific purposes. Small house builders are also being supplied quantities up to 5 tonnes a unit at stockyard prices and for this purpose, some quantities of bars and rods have been earmarked specifically. All these steps are expected to result in improved availability at regulated prices.

Abolition of Octroi in Karnataka

632. SHRI T. R. SHAMANNA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government of India are aware that the Octroi levy has been abolished in the State of Karnataka;

(b) whether there was an assurance that the Central Government would give financial aid to compensate the loss of Octroi revenue;

(c) has the Karnataka State Government approached the Central Government for Financial Assistance; and

(d) if so, whether the Central Government propose to consider it favourably?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) No formal representation has been received from the Government of Karnataka seeking financial assistance to compensate the loss of revenue due to abolition of octroi, although the Finance Minister, Karnataka has in his Budget Speech on the 19th March, 1979 stated that he was assuming that the Centre would compensate 50 per cent of the loss of revenue arising from abolition of Octroi as in the case of prohibition.

(d) In August, 1979, the then Union Finance Minister wrote to the Chief Ministers of all the States stating that due to the constraint on resources it was inadvisable to make additional provisions in the budget for payment of non-Plan grants to the States to compensate them even partially for the loss of revenue arising from the abolition of octroi.

Progress of Kudremukh Project

633. SHRI T. R. SHAMANNA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the progress of Kudremukh Iron Ore Project S. K. Karnataka state:

(b) has Iranian Government fulfilled the obligation as per Agreement entered into; and

(c) steps taken by Government for the compltetion of the project?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) The project proper is now in the final stage of construction.

(b) and (c). The Government of Iran had suspended reimbursement of Iranian Credit for this project from October, 1978 for the ostensible reason that the National Iranian Steel Industries Co., the buyer of concentrate, had not recommended such disbursement, as required under the Financial Agreement. The suspension of the credit and disbursements by the Iranian Government has not affected the progress of construction of the project, as the necessary funds have been made available to the Kudremukh Iron Ore Company Limited by the Government of India.

स्टेनलैस स्टील की चादरों पर आयात शुल्क

634. **श्री दया राम शाक्य :** क्या वित्त मंत्री स्टेनलैस स्टील के चादरों पर आयात शुल्क के बारे में 18 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11442 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित स्टेनलैस स्टील की चादरों पर शुल्क कम करने तथा बढ़ाने के उस प्रश्न पर कोई निर्णय कर लिया है जो सरकार के विचाराधीन रहा है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां। सरकार ने, सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्टेनलैस स्टील की चद्दरों पर आयात-शुल्क मे संशोधन नहीं करने का फैसला किया है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

संगठित और लघु क्षेत्रों में स्टील के तार का निर्माण करने वाले एककों की संख्या

635. **श्री दया राम शाक्य :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित और लघु क्षेत्रों में स्टील के तार का निर्माण करने वाले कितने एकक हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं और वे किस-किस स्थान पर हैं तथा उनमें कितनी पूंजी लगी हुई है,; और

(ख) कपड़ा उद्योग के लिए स्टील के महीन तारों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) कपड़ा उद्योग में कई साइजों और विशिष्टियों के पतले तार इस्तेमाल होते हैं, जिनमें अधिकांश तारों की मांग अधिक नहो है । देश की सभी तार बनाने वाली इकाइयों को अपने उत्पादन में विविधता लाने और 18 एस०डब्ल्यू०जी० से पतले सभी साइजों के तारों का उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है । इस साइज तथा इससे मोटे तारों का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है । जब पर्याप्त मांग न होने के कारण देशीय निर्माताओं के लिए किसी साइज के तार बनाना मितव्ययी नहीं होता तो उदारता पूर्वक आयात की अनुमति दे दी जाती है ।

इस्पात की छड़ों का विनिर्माण करने वाली संगठित तथा लघु क्षेत्र की इकाइयों की संख्या

636. **श्री दया राम शाक्य :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की गोल छड़ें, दार इस्पात छड़ें और मुड़ी हुई इस्पात की छड़ों को बनाने वाली संगठित और लघु उद्योग एककों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने एकक बन्द पड़े हुए हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें वे एकक स्थित हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन एककों द्वारा जो माल उत्पादित किया जा रहा है वह देश में विद्यमान मांग से अधिक है और इसके परिणामस्वरूप ऐसे एकक बन्द हो गये हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार इनके लिए विदेशों में बाजार खोजेगी ?